

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1938 (श0) (सं0 पटना 707) पटना, शुक्रवार, 2 सितम्बर 2016

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

अधिसूचना 16 मई 2016

सं० 5 / निदे0(छात्र0)—23—151 / 16—4061—राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान् छात्र / छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने के लिए योजना, गैर योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना संचालित है। इस योजनाके तहत् विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / संस्थान में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं को छात्रवृति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत् राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।

- 2. यह योजना राज्य के अंदर एवं बाहर सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से संचालित है।
- 3. इस योजना के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं को मुख्य धारा में शामिल किया जाता है तथा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के अंतर्गत राज्य के अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के वैसेछात्र / छात्रा, जिनके माता पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000 / रू० (दो लाख पचास हजार) रू० तक हो, को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2016–17 से राज्य सरकार के सात निश्चय के अनुपालन में स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड (Student Credit Card) के तहत् छात्रों को लाभान्वित किया जाना है।
- 4. राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य के अन्दर एवं बाहर सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव विचारधीन था और राज्य के अंदर एवं राज्य के बहार के सराकरी शिक्षण संस्थानों तथा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में राज्य के अधिकतम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को लाभ पहुँचाने के लिए शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्कों की छात्रवृति दर की अधिकतम सीमा का निर्धारण करने क आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

5. अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र / छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

- (I) भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत् निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015—16 एवं विगत वर्षों में राज्य के अन्दर सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों एवं राज्य के बाहर सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं को संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृति की राशि अनुमान्य की जाएगी।
- (II) भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के तहत् निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015—16 में एवं इसके पूर्व के वर्षों में राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (अधिकतमसीमा रू 15,000/— के अन्तर्गत) पाठ्यक्रम/कोर्स के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि की स्वीकृति निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:—

क्र0	कोर्स की विवरणी	छात्रवृति की राशि की अधिकतम वार्षिक सीमा (देय शिक्षण शुल्क+अनिवार्य शुल्क या निम्न निर्धारित राशि, दोनों में जो न्यूनतम हो)
1	विभिन्न +2 विद्यालयों / महाविद्यालयों में इंटरमीडियट कक्षा यथा—आई०ए० / आई०एस०सी / आई०कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स ।	₹2000 / –
2	स्नातकस्तरीय कक्षा यथा—बी०ए० / बी०एस०सी / बी०कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹5000 / –
3	स्नातकोत्तर कक्षा यथा—एम०ए० / एम०एस०सी० / एम०कॉम / एम०िकल० / पी०एच०डी० एवंअन्य समकक्ष कोर्स ।	₹5000 / –
4	आई०टी०आई०	₹5000
5	त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम / पॉलिटेक्नीक एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹10000 / -
6	व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान के अधीन संचालित कोर्स, यथा—इंजीनियरिंग / मेडिकल / विधि / प्रबंधन तथा अन्य समकक्ष कोर्स (कृषि को छोड़कर)	₹15000 / —

- (III) केन्द्रीय सरकारी शिक्षण संस्थानों (यथा—आई०आई०टी० तथा एन०आई०टी० में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क सिंहत अधिकतम क्रमशः रू० 90,000/—तथा रू० 70,000/— की दर) एवं अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों यथा—नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एन०आई०एफ०टी०, जे०आई०पी०एम०ई०आर०, ए०आई०आई०एम०एस० आदि में अध्ययनरत् छात्र/ छात्राओं के लिए निर्धारितशिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सिंहत अधिकतम रू 75,000/— की दर पर छात्रवृति अनुमान्य होगी एवं निर्धारित शिक्षण एवं अन्य अनिवार्य शुल्क तथा अधिकतम सीमा में जो न्यूनतम होगा, उसी दर पर भुगतेय होगा।
- (IV) मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की तुलना में सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र/ छात्राओं को छात्रवृति स्वीकृति में प्राथमिकता दी जाएगी।
- (V) अनुमानय छात्रवृति राशि के अतिरिक्त समय—समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुरक्षण भत्ता भी देय होगा।

- 6. उपर्युक्त के अनुपालन के क्रम में विहित प्रक्रिया अन्तर्गत सम्यक् जाँचोपरांत संबंधित पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
 - आदेश:— ओदश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रेम सिंह मीणा, सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 707-571+1500-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in